www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 भारत को सनातन ने नहीं, विदेशी...
3 125 यूनिट फ्री बिजली को ले विभाग ने मंसूरचक में...
4 विधानसभा अध्यक्ष ने दी हलके को सौगात...

वर्षः 9 | अंकः 282 | दिल्ली, मंगलवार, 5 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्याः 4 | मूल्यः 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर-मराठी तनाव नहीं: फडणवीस

महाराष्ट्र (एजेन्सी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य में मराठी और गैर-मराठी के बीच कोई तनाव नहीं है तथा दोनों में किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे को से जुड़े भावनात्मक मुद्दे में न पड़ने की सलाह भी दी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में को लेकर विवाद राजनीतिक कारणों से पैदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में के मुद्दे पर दुबे की ओर से पिछले महीने की गई विवादास्पद टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने अपने पार्टी सहयोगी को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि झारखंड से सांसद दुबे को मराठी बनाम गैर-मराठी मुद्दे में नहीं पड़ना चाहिए, जिसे राजनीतिक कारणों से खड़ा किया जा रहा है। फडणवीस ने कहा, हम इससे निपटने में सक्षम हैं। यहां मराठी और गैर-मराठी के बीच कोई तनाव नहीं है।

बरेली में सड़क हादसों में कांवड़िए समेत तीन की मौत, एक अन्य घायल

बरेली (एजेन्सी)। बरेली जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक कांवड़िए समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य के अनुसार रविवार को आंवला-रामनगरमार्ग पर चंपतपुर गांव के 42 वर्षीय धर्मेश कुमार कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जत्थे के साथ कछला घाट से गंगाजल लेकर लौटे थे। वह गांव के बाहर भंडारे में कुछ देर रुके थे, उसी वक्त तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में धर्मेश गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें बरेली अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आर्य के मुताबिक इसके अलावा हाफिजगंज थाना क्षेत्र में सेंथल-हाफिजगंज मार्ग पर कर्बला के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

मेघालय में कार के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत

मेघालय (एजेन्सी)। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक कार के 70 फुट गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक गर्भवती महिला शामिल है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शिलांग-डावकी रोड पर रिंगैन के पास रविवार शाम करीब सात बजे हुई। पुलिस के अनुसार, कार शिलांग से पिनुरस्ला जा रही थी, इस दौरान खतरनाक मोड़ों और कम दृश्यता के कारण चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, हमें संदेह है कि कार में पांच लोग सवार थे, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। कई घंटों के प्रयास के बाद सिर्फ तीन शव बरामद किए जा सके हैं।

ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया: सीएम

विपक्ष ने कभी देशहित की परवाह नहीं की, देश की गरिमा को नीचा दिखाया-रेखा गुप्ता

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव एक सैन्य अभियान नहीं था, वह देश के हर परिवार के सम्मान का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में इन दोनों मसलों पर अपने विचार व्यक्त किए और देश की सैन्य सफलताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और ऐतिहासिक निर्णयों पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' की सफलता को राष्ट्र के गौरव से जोड़ा और भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष का कटघरे में खड़ा किया और कहा कि विपक्ष और उसके नेताओं ने कभी भी देशहित की परवाह नहीं की और भारत की गरिमा को नीचा दिखाने के लिए लगातार षडयंत्र किए। सदन को संबोधित

करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख जनता के भरोसे पर रहती है। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था, उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। प्रधानमंत्री जी ने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल और उसके नेता अपने स्वार्थों के चलते देशहित से लगातार दूर होते जा रहे हैं। इन्हें देश विरोधी ताकतों से प्यार है, जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है। भारत की प्रगति में, भारत के आगे बढ़ने में यह लोग खुश नहीं हैं। ये चाहते हैं कि देश पिछड़ा रहे।

मुख्यमंत्री ने अंत में देश की सेनाओं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए धन्यवाद दिया और सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर पूरे सदन से 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ अपने भाषण का समापन किया।

डीटीसी बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी, ऑटोरिक्शा चालक की मौत

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सोमवार सुबह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस के कथित तौर पर नियंत्रण खो देने और कई वाहनों को टक्कर मारने से 63 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक की मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार नोएडा के सेक्टर-63 निवासी बस चालक नरेंद्र (27) ने संभवतः स्वास्थ्य संबंधी किसी आपात स्थिति के कारण वाहन से नियंत्रण खो दिया। यह दुर्घटना सुबह करीब नौ बजे विकास मार्ग पर मंगल बाजार लाल बत्ती के पास उस वक्त हुई जब डीटीसी बस कथित तौर पर ऑटोरिक्शा और एक कार सहित कम से कम छह-सात वाहनों से टकरा गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ऑटोरिक्शा से टकराने से पहले बस ने कई अन्य वाहनों को टक्कर मार दी।

विकसित करावल नगर मेरा ध्येय है: कपिल मिश्रा

दिल्ली विधानसभा में हुई वरिष्ठ अधिकारियों संग महत्वपूर्ण बैठक

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में करावल नगर क्षेत्र की समस्याओं और विकास योजनाओं को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एंव राजस्व विभाग के जिलाधिकारी ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य करावल नगर में रह रही जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं की समीक्षा और समाधान सुनिश्चित करना था।

बैठक में श्री मिश्रा ने साफ पेयजल की सतत आपूर्ति, जर्जर गलियों के पुनर्निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन, बेहतर सड़क निर्माण और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जलभराव वाले इलाकों की पहचान कर ड्रेनेज लाइनों की समयबद्ध सफाई और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए

जाएं। साथ ही जिन गलियों में वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

ट्रैफिक जाम की समस्या पर चर्चा करते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों का ट्रैफिक ऑडिट कर समाधान केंद्रित योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। स्कूल, बाजार, मुख्य सड़कों और चौराहों के पास बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम तत्काल प्रभाव से उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की स्थिति और कूड़ा प्रबंधन पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

श्री मिश्रा ने बैठक के दौरान कहा विकसित करावल नगर मेरा ध्येय है..इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों संग यह महत्वपूर्ण बैठक की गई है। यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। करावल नगर के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, सुचारु यातायात और प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था-ये किसी पर उपकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है।

श्री मिश्रा ने अधिकारियों से यह भी कहा कि परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए-योजनाएं फाइलों में नहीं, जनता की ज़िंदगी में बदलाव लाएंगी तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा।

भारतीय सेना देश की रक्षक, रक्तदाता जीवन रक्षक: रविन्द्र इंद्राज

सेना, सरकारी अस्पतालों और गैर सरकारी ब्लड बैंक को मिला रक्त

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर जापानी पार्क रोहिणी में आयोजित रक्तदान शिविर 'एक बूँद सेना के लिए' में देश भर से आए रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। श्री इंद्राज ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य पर देश को गर्व है। सेना, देश की रक्षक है और वैसे ही रक्तदाता भी जीवन रक्षक हैं।

समाज कल्याण मंत्री ने इस रक्तदान महाकुम्भ के आयोजन के लिए लक्ष्मी तरू फाउंडेशन, आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए वालंटियर्स की सराहना की। शिविर में रिकॉर्ड 2240 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, इसे सेना, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और गैर सरकारी ब्लड बैंकों के लिए उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर थैलीसीमिया के स्क्रीनिंग के लिए भी रोटरी क्लब की ओर से शिविर लगाया गया।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार 'स्वच्छ दिल्ली-सशक्त दिल्ली' के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज के लिए शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिवर्ष 10 लाख तक के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना लागू की गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अब तक 67 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं और कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी विधानसभाओं में खोले जाएंगे। हॉस्पिटल इन्फॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम से अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी

अपॉइंटमेंट, डिजिटल ओपीडी स्लिप और रीयल-टाइम मेडिकल रिकॉर्ड्स उपलब्ध होंगे। श्री इंद्राज ने इस अवसर पर 'स्वच्छता अभियान-दिल्ली को कूड़े से आजादी' को भी जन सहयोग से सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस माह आजादी के पर्व पर दिल्ली को स्वच्छ बनाने में सहयोग देकर देश के महानायकों को श्रद्धांजलि दें।

इस अवसर पर लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के प्रमुख विपिन गर्ग ने कहा कि 16 राज्यों के 40 से आधिक शहरों से रक्त दाताओं ने देश का अब तक का सर्वाधिक 2240 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। सेना को समर्पित इस आयोजन को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्डस के लिए भेजा गया है।

नायब सरकार ने गरीबों के अपने घर का सपना किया पूरा

नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों को दिया नायाब तोहफा

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा, यह डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0' के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह एक नई सुबह, एक नई शुरूआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का विजन है। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया है। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिला है। यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही नीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि

यह हरियाणा सरकार की एक बड़ी सफलता है कि इन आवास योजनाओं में किसी भी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार को घुसने नहीं दिया। हर चीज डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से किया वादा निभाया, जमीन दी और उस पर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि आज केंद्र व हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कुछ और सेवाएं अथवा सुविधाएं जोड़कर उस योजना का लाभ डबल कर देती है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार, गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में भी 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' के तहत 77,900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। जरूरतमंद परिवारों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। यह सिर्फ एक शुरूआत है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार, बिना छत के न रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। गरीबों को मकान, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान देने वाली योजनाओं से आज हरियाणा एक सशक्त प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब व्यक्ति केवल कल्पना करता था कि क्या कभी उसके सिर पर पक्की छत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जनसेवा की बागडोर संभालने के बाद घोषणा की थी कि अब देश में कोई भी गरीब व जरूरतमंद ऐसा नहीं रहेगा जिसके सिर पर छत न हो और केंद्र सरकार ने पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर देकर उनका सपना पूरा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को प्लॉट और मकान देने का कार्य तेजी से प्रारंभ किया। पहले की सरकारों में तो प्लॉट केवल कागजों में दिखाए जाते थे, परंतु आज रजिस्ट्री और कब्जा दोनों लाभार्थियों को सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए तक है, उन घरों की छत पर दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहले धनराशि खर्च करके सोलर पैनल लगवाना पड़ता था उसके बाद उन्हें सब्सिडी वितरित की जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने गरीबों के हित में ये फैसला किया है कि सोलर पैनल लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा ताकि लाभार्थी इस योजना का लाभ बिना किसी कठिनाई के उठा सकें।

श्री पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का हर बच्चा अपने गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। गांवों में आधुनिक इंडोर जिम भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार हर पंचायत में महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है, जहां वे त्योहारों पर भजन-कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगी।

पूर्व सीएम एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन

उपायुक्त समेत सभी वरीय अधिकारियों एवं कर्मियों ने 02 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा को अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि

संजना भारती संवाददाता
उपेन्द्र गुप्ता

दुमका। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर सोमवार को समाहरणालय सभागार जामताड़ा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक राज कुमार मेहता, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों एवं समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारियों ने 02 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

गौरतलब है कि सोमवार को नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री "दिशोम गुरुजी" शिबू सोरेन का निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे झारखंड में शोक की लहर छा गई है। इसी क्रम में दिवंगत आत्मा की शांति हेतु समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मेहता, उप विकास

आयुक्त निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार सहित अन्य वरीय एवं कनीय पदाधिकारी एवं समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मियों ने 02 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपायुक्त ने कहा कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्य सभा सांसद के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा 4-6 अगस्त तक तीन दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लखेनीय है कि उक्त अवधि में झारखण्ड राज्य के उन सभी भवनों, जहाँ नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाते हैं, पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे एवं किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय 4-5 अगस्त को बन्द रहेंगे।

सम्पादकीय

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी तीखी राजनीतिक बयानबाजी के कारण विवादों में रहते हैं। भारतीय सेना को लेकर दिए गए उनके बयान विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें अपनी बातें संसद के पटल पर रखनी चाहिए, सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर नहीं। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी से पूछा है कि उन्हें कैसे पता चला कि 2,000 किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात संसद में कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि उदय शंकर श्रीवास्तव की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा विवाद के संदर्भ में भारतीय सेना के खिलाफ कई "अपमानजनक बयान" दिए थे। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत और सम्मन आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी कि यह शिकायत राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसे दुर्भावना से दायर किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा (दिसंबर 2022) के दौरान भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल गांधी ने तवांग में हुई झड़प के बाद विवादित बयान देते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार सोई हुई है। उस समय राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक हंगामा तो हुआ ही था साथ ही सेना के पूर्व अधिकारियों ने भी नाराजगी जताते हुए कहा था कि भारतीय सेना दुश्मन से मुकाबले को हमेशा तैयार रहती है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी का ध्यान कांग्रेस शासन के दौरान की कमजोरियों की ओर भी दिलाया था। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी वहां के लोगों ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है और उन पर पूरा भरोसा है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि सिर्फ तवांग ही नहीं, राहुल गांधी ने गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर भी गलतबयानी की थी। उन्होंने उस समय सरकार से पूछा था कि गलवान घाटी कांड के और उसके पहले चीन ने जो हमारी जमीन छीनी है, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? हालांकि राहुल को शायद पता नहीं कि उसके परनाना नेहरुजी के जमाने में हमारी लगभग 38 हजार किमी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था और 1962 के युद्ध में भारत को भारी शार्मिंदगी उठानी पड़ी थी। यही नहीं, पांच-छह दशक के शासन-काल में कांग्रेस पार्टी ने उस जमीन की वापसी के लिए कभी कोई ठोस कोशिश ही नहीं की। तवांग घटना के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से जो सात सवाल पूछे थे वह राष्ट्रहित के विरुद्ध तो थे ही साथ ही हमारी सेना का मनोबल गिराने वाले भी थे। राहुल गांधी को यह भी पता होना चाहिए कि साल 2007 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बताया था कि 38 हजार स्क्वयार किलोमीटर की जमीन और कुल 43180 स्क्वयार किलोमीटर जमीन कांग्रेस शासन के दौरान चीन ने कब्जाई है। देखा जाये तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की टिप्पणी पर न्यायपालिका ने सवाल खड़े किए हों। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी "चौकीदार चोर है" वाली टिप्पणी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। अब तवांग घटना और चीन से जुड़ी सीमा स्थिति पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले उनके बयान ने एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी की सीमाओं पर बहस छेड़ दी है।

जयंती

द्वारका प्रसाद मिश्रा

जन्म-5 अगस्त, 1901, उन्नाव, उत्तर प्रदेश; मृत्यु-31 मई, 1988, दिल्ली) भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। द्वारका प्रसाद मिश्रा महात्मा गाँधी के 'असहयोग आन्दोलन' से जुड़ गये थे। राष्ट्रवादी आन्दोलनों में उन्होंने सक्रियता से अपना योगदान दिया था। जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों के कारण इन्हें तेरह वर्षों तक राजनीतिक वनवास भोगना पड़ा। इन्होंने कई ऐतिहासिक शोध ग्रंथ भी लिखे थे। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत साहित्य से द्वारका प्रसाद जी को बहुत लगाव था।

पुण्यतिथि

गोपीनाथ बोरदोलोई

जन्म-10 जून, 1890; मृत्यु-5 अगस्त, 1950) भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें 'आधुनिक असम का निमार्ता' भी कहा गया है। इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1941 ई. में 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास जाना पड़ा था। वर्ष 1942 ई. में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भागीदारी के कारण गोपीनाथ बोरदोलाई को पुन: सजा हुई। गोपीनाथ ने असम के विकास के लिए अथक प्रयास किये थे। उन्होंने राज्य के औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया और गौहाटी में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना करवायी। असम के लिए उन्होंने जो उपयोगी कार्य किए, उनके कारण वहाँ की जनता ने उन्हें 'लोकप्रिय' की उपाधि दी थी। वस्तुत: असम के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

कल मिलेंगे

एक बार सोनू अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाता है...
दोनों सुहाने मौसम में चाय पी रहे होते हैं, इतने में सोनू अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ पूछता है...
सोनू की गर्लफ्रेंड-चुप करो, मुझे मौसम का आनन्द लेने दो...
सोनू-लेकिन मैं तो...
गर्लफ्रेंड-जो भी कहना है चाय पीने के बाद कहना
गर्लफ्रेंड-(चाय पीने के बाद)-कहो जो कहना था...
सोनू-तुम्हारी चाय में मक्खी गिरी हुई थी.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

भारत को सनातन ने नहीं, विदेशी आक्रांताओं और कांग्रेस ने बर्बाद किया

सांसद संबित पात्रा ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के ताजा विवादित बयान का हवाला देते हुए कहा कि "आव्हाड महाराष्ट्र के नेता हैं और शरद पवार की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपने सत्य का अपमान किया है, शिव के खिलाफ बोला है और उस भारत की सुंदरता का विरोध किया है। वह भारत जिसकी खूबसूरती सबके सम्मान में निहित है

-कमलेश पांडेय

भारतीय पृष्ठभूमि वाली दुनिया की सबसे पुरातन सभ्यता-संस्कृति 'सनातन धर्म" पर सियासी वजहों से जो निरंतर हमले हो रहे हैं, उनका समुचित जवाब देने में अब कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अन्यथा इसकी सार्वभौमिक स्थिति और महत्ता को दरकिनार करने वाले ऐसे ही बेसिरपैर वाले क्षुद्र सवाल उठाए जाते रहेंगे।

हाल ही में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और अवसरवादी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक नया विवाद छेड़ते हुए जो कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया और इसकी विचारधारा को विकृत बताया, वह निहायत ही बेहूदगी भरी, अपरिपक्व और पूर्वाग्रह ग्रसित बयानबाजी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है।

वहीं, भारत की आत्मा समझी जाने वाली सनातन सभ्यता-संस्कृति पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनकी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करते हुए उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, अन्यथा चुनाव आयोग को ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे सम्बन्धित राजनीतिक दल की मान्यता अविलंब समाप्त की जानी चाहिए।

अन्यथा जनमानस में यही संदेश जाएगा कि भारतीय संविधान के मातहत जारी कार्यपालिका प्रशासन और न्यायपालिका प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता की पक्षधरता करने वाले ऐसे ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हैं, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता-संस्कृति के हमलावरों पर भी उसी तरह से उदार हैं, जैसे कभी मुगल या अंग्रेज प्रशासक या कांग्रेसी राजनेता हुआ करते थे। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विधायक का यह बयान 2008 मालेगाव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों के विशेष एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आया है, जिसने भगवा/हिन्दू आतंक शब्द को लेकर पिछले डेढ़ दशकों से जारी राजनीतिक बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। यह अजीबोगरीब है कि पत्रकारों से बात करते हुए आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। कभी कोई धर्म सनातन धर्म नाम से नहीं था। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। यही कथित सनातन धर्म था जिसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में बाधा डाली। इसी सनातन धर्म ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। इसी सनातन धर्म के अनुयायियों ने ज्योतिराव फुले की हत्या का प्रयास किया।

इन्होंने सावित्रीबाई फुले पर गोबर और गंदगी फेंकी। यही सनातन धर्म शाहू महाराज की हत्या की साजिश में शामिल था। इसने आंबेडकर को पानी पीने या स्कूल में पढ़ने की अनुमति तक नहीं दी। वहीं, आव्हाड के सनातन धर्म और सनातन समाज विरोधी बयान पर राणे और संजय निरुपम ने भी ठोककर जवाब दिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर कहा कि 'हिंदू आतंकवाद' या 'सनातनी आतंकवाद' जैसी भाषा भारत की हिंदू और संत परंपरा को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई एक परिभाषा है।

राणे की इस प्रतिक्रिया का लब्बोलुआब यह है कि हिन्दू समाज के प्रति हद से ज्यादा नकारात्मक हो चुकी कांग्रेस को देशवासियों ने सजा दी, और केंद्रीय सत्ता से बाहर कर दिया, जिससे कांग्रेसी बौखलाये हुए हैं। उसके लोग मुस्लिम वोटों को समाजवादियों से खींचने के लिए रणनीतिक गलतियां दर गलतियां करते जा रहे हैं। ऐसा करके वे लोग विपक्ष की राजनीति तो कब्जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता 15 साल बाद भी उनके लिए दिल्ली दूर ही साबित होगी।

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के तथाकथित "इकोसिस्टम" पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सनातन धर्म को बदनाम करने और हिंदू आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आमादा है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के उन हालिया बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने सनातन आतंकवाद का नया जुमला गढ़ा है।

सांसद संबित पात्रा ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के ताजा विवादित बयान का हवाला देते हुए कहा कि, "आव्हाड महाराष्ट्र के नेता हैं और शरद पवार की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपने सत्य का अपमान किया है, शिव के खिलाफ बोला है और उस भारत की सुंदरता का विरोध किया है। वह भारत जिसकी खूबसूरती सबके सम्मान में निहित है। मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी पार्टी भी यही सोचती है, स्पष्ट कीजिए।"

वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए खूब सारी फर्जी कहानियां सुनाई हैं। वे यह बताना भूल गए कि अगर सनातन धर्म नहीं होता तो वे अब तक जितेंद्र नहीं जितुद्दीन हो जाते। अगर सनातनी नहीं होते तो देश सऊदी अरब बन जाता। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भगवा शब्द की जगह सनातन या हिंदुत्ववादी शब्दों के उपयोग की वकालत की है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी दोषियों को बरी किए जाने के बाद चव्हाण ने सनातन संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता का हवाला देते हुए उस पर प्रतिबंध का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के लिए 'भगवा' शब्द का प्रयोग न करके 'सनातन' या 'हिंदुत्ववादी' शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्होंने अपने विचारों के समर्थन में ऐतिहासिक संदर्भ भी दिए।

चव्हाण ने कहा, 'मेरे मुख्यमंत्री काल में ह्यसनातन' संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता थी।' इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने एक गोपनीय रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी। उसी संदर्भ में मैंने ह्यसनातन' शब्द का उपयोग किया था, क्योंकि उस संगठन का कार्य आतंकवादी प्रवृत्ति का था। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था।' उन्होंने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर और कॉ. गोविंद पानसरे की हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ क्या हुआ और आज तक न्याय क्यों नहीं मिला, यह गंभीर प्रश्न है। उन्होंने सवाल उठाया और कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी थी, उसी समय मुंबई सीरियल ब्लास्ट और मालेगांव फैसले का आना संयोग है या साजिश? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब मालेगांव केस चल रहा था, तब जो बयान दिया था, उसका असर कोर्ट के निर्णय पर पड़ा हो, तो यह गंभीर मामला है। चव्हाण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'बीते 15 वर्षों से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन इस अवधि में जांच एजेंसियों ने न्यायोचित कार्य नहीं किया है। ये सब सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है।' मुंबई विस्फोट और मालेगांव दोनों मामलों में सरकार को उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए।'

चव्हाण के अनुसार, कोई भी धर्म आतंकवादी नहीं होता, लेकिन नाथूराम गोडसे की विचारधारा संघ की थी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक समय संघ पर प्रतिबंध लगाया था।उन्होंने यह भी साफ किया कि चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ने ह्यभगवा आतंकवाद' शब्द का उपयोग किया था, लेकिन मैं और मेरी पार्टी उस शब्द से सहमत नहीं थे और आज भी नहीं हैं। इसलिए सनातनी आतंकवाद कहते हैं।

तल्ख हकीकत यह है कि भारत को सनातन ने नहीं, विदेशी आक्रांताओं और कांग्रेस ने बर्बाद किया। आजादी की प्राप्ति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए तत्कालीन हिंदूवादी कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ छल किया। जबतक हिन्दू समाज इसे समझ पाया, तबतक बहुत देर हो चुकी थी। हिन्दू हित के जो कार्य 1947 में ही शुरू कर दिए जाने चाहिए थे, वो 1998-99 में प्रारंभ हुए, लेकिन उन्हें सही गति 2014 के बाद मिल पाई।

अभी भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता इस राह में सबसे बड़ा बाधक है। यह इस्लामिक व ईसाइयत को संरक्षण देता है तो हिंदुओं को सिख, बौद्ध, जैन आदि पंथ को धर्म ठहराकर तोड़ता है। इससे हिन्दू समाज आंदोलित है। उसे योगी शासन का इंतजार है, ताकि यूपी की तरह पूरे देश का कायाकल्प संभव हो सके।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

झालावाड़ में स्कूली हादसे से भी नहीं खुलेगी नेताओं की नींद?

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने हाल ही आठ हजार स्कूलों का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा परिषद को भेजा। इनमें से महज दो हजार स्कूलों का चयन कर इनमें मरम्मत के लिए 175 करोड़ प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया, लेकिन राशि अभी तक नहीं मिली। इस बार केंद्र से सिर्फ नवीन भवनों का बजट मिला। इसके चलते सरकार ने पिछले बजट में 700 स्कूलों की मरम्मत की घोषणा की

-योगेन्द्र योगी

देश के सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता की हालत करेला और नीम चढ़ा जैसी है। हालात ये हैं घिसी-पिटी, आधी-अधूरी शिक्षा ग्रहण करने वाले इन स्कूलों में बच्चों की जान तक महफूज नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक के पलोदी गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। राज्य के सैकड़ों स्कूलों के संस्था प्रधान पिछले दो साल से विभाग से भवनों की मरम्मत के लिए बजट मांगते-मांगते थक गए, लेकिन सरकारी तंत्र पर कोई असर नहीं हुआ।

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने हाल ही आठ हजार स्कूलों का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा परिषद को भेजा। इनमें से महज दो हजार स्कूलों का चयन कर इनमें मरम्मत के लिए 175 करोड़ प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया, लेकिन राशि अभी तक नहीं मिली। इस बार केंद्र से सिर्फ नवीन भवनों का बजट मिला। इसके चलते सरकार ने पिछले बजट में 700 स्कूलों की मरम्मत की घोषणा की। इसके लिए 80 करोड़ जारी हो गए, जिनका कार्य चल रहा है। वहीं, हाल ही बजट में 175 करोड़ स्वीकृत किए गए। लेकिन बजट कम होने के कारण दो हजार स्कूलों को शामिल किया गया। करीब छह हजार स्कूल मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले राजस्थान में ही सरकारी स्कूलों के भवनों की ऐसी दुर्दशा है। देश में 54 हजार से अधिक सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। इन स्कूलों में लाखों बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। ओडिशा में 12 हजार 343, महाराष्ट्र में 8 हजार 71, पश्चिम बंगाल में 4 हजार 269, गुजरात में 3 हजार 857, आंध्र प्रदेश में 2 हजार 789, मध्य प्रदेश में 2 हजार 659, उत्तर प्रदेश में 2 हजार 238 और राजस्थान में 2 हजार 061 स्कूल जर्जर हालत में हैं। इनमें कभी भी झालावाड़ जैसे हादसे की पुनरावृत्ति हो सकती है। राजस्थान में हुए स्कूली हादसे की पुनरावृत्ति देश के कई राज्यों में पूर्व में हो चुकी है। भोपाल के एक स्कूल में छत से प्लास्टर गिरने से छात्राएं घायल हो गईं। झारखंड की राजधानी रांची में एक स्कूल की इमारत की खिड़की का एक हिस्सा टूटकर गिरा था। उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों की दीवारों में दरारें हैं और ऑपरेशन कायाकल्प का असर नहीं दिख रहा। बिहार में कई बच्चों के पास स्कूल की इमारत तक नहीं है और वे झोपडियों में पढ़ते हैं, जहाँ पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। मध्य प्रदेश के सतना में भी प्लास्टर गिरने से एक बच्चा घायल हुआ था।

सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी खराब है। यूडाइस की रिपोर्ट और प्रधानमंत्री पोषण योजना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सरकारी स्कूलों में डेढ़ करोड़ बच्चे कम हुए और इस साल तो मामला और गंभीर हुआ है। 23 राज्यों में बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया है। इनमें से राजस्थान सहित 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ ये घटत, एक लाख से ज्यादा की है। अर्थात लाखों बच्चों ने स्कूल छोड़ा। इनमें उत्तर प्रदेश में (21.83 लाख), बिहार (6.14 लाख), राजस्थान (5.63 लाख) और पश्चिम बंगाल (4.01 लाख) और कर्नाटक (2.15 लाख) बच्चों ने स्कूलों से मुंह मोड़ लिया। असम, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और गुजरात की हालत भी यही है। साल 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत में 14.72 लाख स्कूल हैं, जिनमें 24.8 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और 98 लाख शिक्षक हैं। अब 57.2 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर हैं, 53 प्रतिशत में इंटरनेट है। प्राथमिक कक्षाओं से 1.9 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से 5.2 प्रतिशत और सेकेंडरी लेवल से 14.1 प्रतिशत बच्चे हर साल पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये सर्वे, पहले के मुकाबले स्कूलों की बेहतरी दिखा रहे थे। मगर हाल में नज? आ रही गिरावट ने ये सारी बात उलट दी। भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। शोध अध्ययनों से पता चला है कि छात्रों की अनुपस्थिति दर बहुत अधिक है और उसकी तुलना में आधे से भी कम शिक्षक वास्तव में पढ़ा रहे थे। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 5 के छात्र कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं या साधारण गणितीय प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले दो दशकों में शिक्षा में अधिक धन लगाया है, लेकिन अधिक व्यय, उच्च शिक्षक-छात्र अनुपात, पाठ्यक्रम परिवर्तन और एनजीओ के प्रयासों के बावजूद, पिछले दशक में एएसईआर के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। वर्ष 2009 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम स्कूल रैंकिंग में भाग लिया। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि 15 वर्षीय स्कूली बच्चे विज्ञान-गणित और पढ़ने में कैसा प्रदर्शन करते हैं। भारत 74 देशों में से 72वें स्थान पर रहा, जो इसकी शिक्षा प्रणाली का प्रतीक है।

भारत ने इसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लेना बंद कर दिया। हालांकि 2021 में प्रतियोगिताओं में भारत ने फिर से भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसी बीच कोरोना की लहर आ गई और आगे कुछ नहीं हुआ। भारत के कुछ प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में लंबे समय से गुणवत्ता स्थापित है। अधिकांश राज्य सरकार के स्कूलों के साथ ऐसा नहीं है। ये इतनी खराब गुणवत्ता के हैं कि कई गरीब परिवार अपने बच्चों को मुफ्त सरकारी स्कूलों से निकालकर महंगे निजी स्कूलों में डाल देते हैं, भले ही इनकी अक्सर संदिग्ध साख हो। केंद्रीय विद्यालय अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि माता-पिता प्रभावशाली सिविल सेवक होते हैं जो शिक्षकों की माता-पिता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए समय-समय पर कई आयोग और समितियों का गठन किया गया है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन आयोगों और समितियों में कोठारी आयोग, यशपाल समिति, और टीएसआर सुब्रमण्यम समिति प्रमुख हैं। इनकी सिफारिशों में शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार, शिक्षकों की भूमिका, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में बदलाव और शिक्षा में नवाचार शामिल हैं। इन आयोगों की रिपोर्ट धूल फांक रही है। कारण स्पष्ट है कि सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए शिक्षा में सुधार से वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। जब तक देश में शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता रहेगा, तब तक देश में शिक्षा का सर्वांगीण उत्थान संभव नहीं है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का ट्रंप ने फिर लिया श्रेय, कहा-मैंने 5 युद्धों को कराया समाप्त

(एजेन्सी)।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने का श्रेय लिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव भी शामिल है। 10 मई से, ट्रंप बार-बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कथित तौर पर वाशिंगटन की मध्यस्थता से हुई बातचीत के बाद दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पूर्ण और तत्काल युद्धविराम कराने में मदद की। हालांकि, भारत ने युद्धविराम में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को बार-बार खारिज किया है और कहा है कि किसी भी विदेशी नेता ने भारत से अपने सैन्य अभियान रोकने के लिए नहीं कहा।

ट्रम्प के नवीनतम दावे व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के उस बयान के तुरंत बाद आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम सहित दुनिया भर में शांति समझौते कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर रेडियो होस्ट और लेखिका शारलेमेन द गॉड की आलोचना करते हुए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि शारलेमेन ट्रंप की उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं जानतीं, जिसमें पाँच युद्धों का अंत भी शामिल है, जैसे कि कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच 31 साल पुराना संघर्ष, जिसमें 70 लाख लोग मारे गए थे।

ट्रंप ने आगे कहा, "उन्हें यह सब नहीं पता था, न ही भारत और पाकिस्तान के बारे में, न ही ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करने के बारे में, न ही भयावह खुली सीमा को बंद करने के बारे में, न ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में।" एक दिन पहले ही ट्रंप ने न्यूजमैक्सपर एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने बहुत सारे युद्धों को खत्म कराया है। ट्रंप ने कहा, अगर आप हाल में हुई घटनाओं पर नजर डालें, तो पाएंगे कि हमने कई मामलों को सुलझाया है कई बेहद गंभीर युद्ध खत्म कराए हैं इनमें से एक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच था, जिसमें परमाणु टकराव की आशंका थी।

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के साथ-साथ कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष को भी सुलझाया है। ट्रंप ने कहा, मैंने उस मामले को सुलझाया। और मैंने इसे व्यापार के जरिए सुलझाया। मैंने कई ऐसे मामलों को व्यापार की मदद से सुलझाया। मैंने कहा, सुनो, आप लोग लड़ सकते हो, जितना चाहे लड़ो, लेकिन हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे।उन्होंने कहा, अचानक वे लोग युद्ध रोक देते हैं। मैंने कई युद्ध सुलझाए हैं।

ट्रंप शुल्क से तीस प्रतिशत घट सकता है भारत का अमेरिका को निया़र्त: जीटीआरआई

(एजेन्सी)।
शोध संस्थान जीटीआरआई ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत का अमेरिका को निर्यात 30 प्रतिशत घटकर 60.6 अरब डॉलर रह सकता है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीटीआरआई ने सरकार को ब्याज समानीकरण योजना को पुनर्जीवित करने, एक हेल्पडेस्क बनाने, व्यापार समझौतों का रणनीतिक उपयोग करने और नए निर्यातकों को शामिल करने का सुझाव दिया। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क चीन के बाद सबसे अधिक है। अमेरिका ने चीन पर 30 प्रतिशत, वियतनाम पर 20 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 18 प्रतिशत, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस पर 19 प्रतिशत, तथा जापान और दक्षिण कोरिया पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर शुल्क से ज्यादातर क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को नुकसान होगा। अमेरिका की नयी शुल्क व्यवस्था में दवा, ऊर्जा उत्पाद, महत्वपूर्ण खनिज और सेमीकंडक्टर शामिल नहीं हैं।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, भारतीय वस्तुओं पर दबाव है। इसके चलते अमेरिका को भारत का निर्यात लगभग 30 प्रतिशत घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 60.6 अरब अमेरिकी डॉलर रह सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को निर्यात 86.5 अरब अमेरिकी डॉलर था।

जीटीआरआई का अनुमान है कि भारत का परिधान निर्यात सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में एक होगा। इसके अलावा झींगा निर्यात, आभूषण निर्यात और धातु निर्यात को भी नुकसान होगा।

अमन कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में डेब्यू के लिए तैयार

(एजेन्सी)।
पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत (57 किग्रा) को विश्व चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में कोई खास चुनौती नहीं मिली तो वहीं सुजीत कलकल ने शानदार कौशल दिखाते हुए सोमवार को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। क्रोएशिया के जगरेब में अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप 2024 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य जीतने के बाद सहरावत का विश्व स्तर का दूसरा टूर्नामेंट होगा।

इस 22 साल के पहलवान ने जून में प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी करते हुए मंगोलिया रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक जीता था। वह हालांकि यहां ट्रायल में मंगोलिया की तुलना में कहीं बेहतर नजर आये। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में सुमित के खिलाफ मात्र एक अंक गंवाने के बाद शुरूआती पीरियड में ही तकनीकी श्रेष्ठता से जीत दर्ज की। उन्होंने फाइनल में राहुल को एकतरफा अंदाज में बिना कोई अंक गवायें तकनीकी श्रेष्ठता से मात दी।

अमन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट आया हूं। मेरी फिटनेस अच्छी है और मेरी लय भी वापस आ गई है। मैं विश्व चैंपियनशिप के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैंने मंगोलिया रैंकिंग सीरीज में कुछ गलतियां की थी लेकिन वह एक साल बाद मेरी पहली प्रतियोगिता थी। मुझे लगता है कि मैंने इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया था, मैं एक समय 11-6 से आगे भी चल रहा था, लेकिन मैं उस हार (मंगोलिया में) को स्वीकार करता हूं।

पुरुषों की 65 किग्रा स्पर्धा में काफी करीबी मुकाबला देखने को मिला जहां सुजीत कलकल ने बाजी मारी। सुजीत ने अनुज (10-0) और विशाल कालीरमन (8-4) के खिलाफ अपने मजबूत रक्षात्मक खेल से प्रभावित किया। वह मुश्किल स्थिति से जवाबी हमला करके अंक बटोरने में सफल रहे। बजरंग पुनिया के हटने के बाद 65 किग्रा में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन लचर रहा है लेकिन सुजीत ने इस प्रदर्शन से उम्मीदें जगा दी है। तोक्यो ओलंपिक में 86 किग्रा में चुनौती पेश करने वाले दीपक पूनिया ने 92 किग्रा के अपने नये भार वर्ग में दबदबा कायम करते हुए विश्व चैंपियनशिप का टिकट कटाया। केतली पहलवानके नाम से मशहूर दीपक ने महज 73 सेकंड में मंजीत को हराने के बाद हरियाणा के सचिन को परास्त किया। अंडर 20 चैंपियन मुकुल दाहिया भी सीनियर टीम में जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने 86 किग्रा में सचिन जगलान और आशीष को एकतरफा अंदाज में हराया।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान

(एजेन्सी)। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। इस 24 सदस्यीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के कंधों पर होगी। वहीं ये दौरा 15 से 21 अगस्त तक चलेगा। वहीं इस टीम में पूवन्ना सीबी बतौर नया चेहरा होंगे। अगले साल नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप क्वालीफायर टूर्नामेंट में जो 29 अगस्त को बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। टीम की कमान ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत कौर के ही पास है, जबकि गोलकीपिंग का जिम्मा कृशन पाठक और सूरज करकेरा संभालेंगे। वहीं डिफेंस में सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, अमित रोहिदास, नीलम संजीप सेस, जुगराज सिंह और नए खिलाड़ी कर्नाटक के पूवन्ना होंगे। वहीं टीम में मिडफील्डर में युवा राजिंदर सिंह को शामिल किया गया है जिनकी अक्सर तुलना पूर्व कप्तान सरदार सिंह से होती है। उनके अलावा राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, रबिचंद्र सिंह मोइरांगथम, विष्णु कांत सिंह भी मिडफील्ड में होंगे। फॉरवर्ड पंक्ति में मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, सेल्वम कार्ति और आदित्य लालागे रहेंगे। एशिया कप से पहले इस दौरे की अहमियत के बारे में मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा कि, हमारा फोकस शारीरिक अनुकूलन बेहतर करने और तकनीकी पहलुओं पर रहेगा। टीम में युवा खिलाड़ियों को चुने जाने के बारे में उन्होंने आगे कहा कि, हमने कुछ युवाओं को दबाव में खेलने की उनकी क्षमता परखने और जरूरी एक्सपोजर देने के लिये चुना है। भारतीय टीम आठ अगस्त को बेंगलुरू से आस्ट्रेलिया रवाना होगी जहां भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र पर शिविर चल रहा है।

टीम इस प्रकार है-गोलकीपर: कृशन बी पाठक और सूरज करकेरा
डिफेंडर: हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, अमित रोहिदास, नीलम संजीप सेस, जुगराज सिंह, पूवन्ना सीबी मिडफील्डर : राजिंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, रबिचंद्र सिंह मोइरांगथम, विष्णु कांत सिंह फॉरवर्ड: मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, सेल्वम कार्ति और आदित्य लालागे।

महावतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धूम

(एजेन्सी)। अश्विन कुमार की फिल्म महावतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। प्रह्लाद महाराज और भगवान विष्णु के प्रचंड नरसिंह अवतार की महाकाव्य कथा पर आधारित इस एनिमेटेड पौराणिक नाटक ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है और रिलीज के मात्र 10 दिनों के भीतर 91.25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है। यह फिल्म अब भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'स्पाइडर-मैन' और 'कुंग फू पांडा' जैसी अंतरराष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। Sacnilk.com के आंकड़ों के अनुसार, इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 112 करोड़ रुपये है। Sacnilk.com के नवीनतम अपडेट के अनुसार, महावतार नरसिम्हा ने अपने दूसरे शनिवार को 15.4 करोड़ रु की कमाई की। इसने पिछले दिन की तुलना में 100% की वृद्धि दिखाई, जिस दिन इसकी कमाई 7.7 करोड़ रु थी। दूसरे हफ़्ते में इतनी जबरदस्त वृद्धि फि ल्म देखने वाले प्रशंसकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया का संकेत देती है, जिससे फि ल्म को और बढ़ावा मिला है। 3 अगस्त के अंत तक महावतार नरसिम्हा की एक दिन की कमाई में और इजाफा होने की उम्मीद है। अब तक इसने 13.4 करोड़ रु (शाम 6.30 बजे तक) कमा लिए हैं। अब तक कुल कमाई 81.25 करोड़ रु हो गई है। किसी भी एनिमेटेड फि ल्म के लिए यह आश्चर्यजनक वृद्धि है, खासकर जब फि ल्म को अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2, विजय देवरकोंडा की किंगडम और सिद्धांत चतुर्वेदी-तृप्ति डिमरी की धड़क 2 जैसी नई रिलीज से कड़ी टक्कर मिल रही है।

125 यूनिट फ्री बिजली को ले विभाग ने मंसूरचक में लोगों को किया जागरूक

अब हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट बिजली निःशुल्क

एसबी संवाददाता

मंसूरचक। नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा सोमवार को मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर दो में विशेष जागरुकता अभियान चलाया। मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा घोषित 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के तहत आम लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। जहां विभागीय कमीर्यों के द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई गई। बिजली विभाग जेई हर्ष कुमार मौर्य ने कहा कि अब प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिमाह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।

इस योजना से होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि 125 यूनिट तक बिजली खपत करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन उसके ऊपर की खपत पर सामान्य दर से बिजली बिल का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। सरकार के इस पहल का उद्देश्य गरीब व मध्यवर्गीय परिवार को राहत देना है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अनावश्यक बिजली की खपत से बचें व इस योजना का लाभ उठावें। मौके पर सभी कर्मी मौजूद थे।

जमुई जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई के जिला पदाधिकारी नवीन ने समाहरणालय परिसर स्थित सभा कक्ष मे विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में डीएम ने कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, गव्य विभाग, पशु विभाग, सहकारिता विभाग, खाद उपभोक्ता संरक्षण विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छता विभाग, गन्ना विभाग, जल संसाधन विभाग, कल्याण विभाग, सांख्यिकी विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कल्याण विभाग जीविका, शस्त्र विभाग, मध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, खेल विभाग, आईसीडीएस, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कला संस्कृति विभाग, तथा विद्युत विभाग, योजना एवं विकास विभाग, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र समेत सभी संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए गये।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली एवं कार्यालय द्वारा संचालित कार्यों के क्रियान्वयन के विषय में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने किसान भवन के विषय में भी जानकारी दी। जिस पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के बरहट प्रखंड को छोड़कर शेष सभी नौ प्रखंडों में किसान भवन बना है, बरहट प्रखंड में किसान भवन बनाने हेतु विभाग को प्रस्ताव गया हुआ है। तथा राज्य में जिले की रैंकिंग 29 वां स्थान पर है।

वहीं उन्होंने मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में भी फीडबैक लिया, इस दौरान जलाशय संबंधी, भ्रमण दर्शन तालाव निर्माण, चयन प्रक्रिया में आये हुए आवेदन के विषय में जानकारी ली तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। सरकार के सात निश्चय 2 के लक्ष्य को पूरा करने हेतु गव्य विभाग के पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जिले के सिकंदरा एवं झाझा प्रखंड अंतर्गत जमीन उपलब्ध नहीं रहने कारण संचालित योजनाओं को अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को निर्देशित किया कि वह अपने स्तर से इसे देख ले। आगे उन्होंने पशुपालन पदाधिकारी से जिले में संचालित पशु अस्पताल की स्थिति का फीडबैक लिया। इस पर पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 21 पशु अस्पताल हैं जमुई को लेकर 22 हैं। मोबाइल एंबुलेंस सभी प्रखंडों में संचालित हैं, पशु चारा के लिए टेंडर प्रक्रिया किया जाता है। जिलाधिकारी ने खाद्द उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत लोगों को नये राशन कार्ड की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लघु सिंचाई अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट, जल जीवन हरियाली से संबंधित क्रियान्वित कार्य की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी,उप समाहर्ता भूमि सुधार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कैथल जिले में इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड कोचिंग परीक्षा संपन्न, 2,042 विद्यार्थियों ने लिया भाग

कक्षा 7वीं से 11वीं तक प्रत्येक कक्षा के शीर्ष 8 विद्यार्थियों का किया जाएगा चयन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिला गणित विशेषज्ञ कैथल छत्रपाल ने बताया कि जिले में सोमवार को इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड कोचिंग परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा जिले के 6 ब्लॉक मुख्यालय विद्यालयों में एक साथ आयोजित हुई, जिसमें कुल 2,042 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा संचालन की व्यवस्था में संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य परीक्षा अधीक्षक रहे, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी सह ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर ने ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेदारी निभाई। प्रत्येक ब्लॉक में नियुक्त नोडल गणित अध्यापकों ने परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परीक्षा उपरांत सभी प्रश्न पत्र बीआरसी कार्यालयों में जमा करवा दिए गए। जिला गणित विशेषज्ञ कैथल

छत्रपाल ने बताया कि 5 अगस्त 2025 को सुबह 9:00 बजे आईएमओ कोचिंग की पूरी टीम बीआरसी कार्यालयों में एकत्र होकर कॉपियों की जांच करेगी। इसी समय सभी नोडल अधिकारियों को आंसर की उपलब्ध करवाई जाएगी। जांच प्रक्रिया के तहत पहले प्रश्न पत्र और आंसर-की का मूल्यांकन व सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ सही पाया गया तो मार्किंग शुरू होगी, अन्यथा विसंगतियों को जिला गणित विशेषज्ञ के संज्ञान में लाकर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। जिला गणित विशेषज्ञ कैथल छत्रपाल ने बताया कि परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा 7वीं से 11वीं तक प्रत्येक कक्षा के शीर्ष 8 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इस संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। चयनित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, स्कूल प्राचार्यों और आईएमओ टीम के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त कैथल श्री दीपक बाबूलाल करवा करेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी स्वयं पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे।

ओरिएंटेशन के बाद प्रत्येक ब्लॉक में चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का समय-निर्धारण किया जाएगा। सभी कक्षाओं (7वीं से 11वीं) के लिए एक समान सिलेबस तैयार किया जाएगा तथा प्रतिमास परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री छत्रपाल जिला गणित विशेषज्ञ कैथल रहेंगे।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार हुए सम्मानित

एसबी संवाददाता

मंसूरचक। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंसूरचक के द्वारा गर्भवती महिलाओं का मासिक प्रसव पूर्व जांच एवं 30 वर्ष एवं उसके ऊपर के आयु के सभी व्यक्तियों का डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर का जांच दिए गए लक्ष्य के अनुरूप सत्य प्रतिशत उपलब्धि करने के उपरांत उत्कृष्ट कार्य जिला स्तर पर करने हेतु जिलाधिकारी तुषार सिंगला के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ केंद्र मंसूरचक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार एवं हेल्थ वेल्नेस सेंटर साठा की एनएम रुबी कुमारी को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। डॉ. विनय कुमार ने इस कार्य हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिवार के कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें आमजन: डीसी प्रीति

डीसी ने ली बैठक, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार आमजन में देशभक्ति की भावना को ओर मजबूत एवं प्रबल करने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान तीन चरणों में 15 अगस्त 79 वें स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में कई गतिविधियां और प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगीं। इसमें रंगोली प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, तिरंगा सेल्फी, सैनिकों को राखियां और चिट्ठियां भेजना और अपने घरों, सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराना मुख्य रूप से शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिन जिन विभागों की ड्यूटी लगाई है, संबंधित विभाग उसे जिम्मेदारी के साथ निभाएं। इस अभियान में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग मुख्य थीम रहेगा।

डीसी प्रीति सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहीं थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय और महानिदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत पहले चरण में 8 अगस्त तक विभिन्न स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि में प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। स्कूल, कालेज व सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। थल सेना, वायुसेना और

उपायुक्त कैथल प्रीति।

जल सेना को तिरंगा राखियां और चिट्ठियां भेजी जाएंगी। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी चिट्ठी भेजी जाएगी। डीसी ने बताया कि दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त के बीच आयोजित होगा। इसमें रैली/तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा।

आगामी 11 अगस्त तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिस विभाग में स्वच्छता संबंधी कार्य ठीक नहीं मिला तो उन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शहीदों के परिजनों को भी इस अभियान में जोड़ा जाएगा। जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। डीसी प्रीति ने बताया कि अभियान के तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में तिरंगा लगाने जैसी व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डीसी ने आमजन का आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रियता से भाग लें, ताकि अभियान को सार्थकता के साथ सफल बनाया जा सके।

डीसी प्रीति कहा कि हर घर तिरंगा पहल का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की गहरी भावना ओर अधिक मजबूत करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह अभियान जनसहभागिता से चलाया जाएगा। उन्होंने सभी से इस अभियान को पूरे जोश, उत्साह और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाने का आग्रह किया।

एसएससी परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर कुमारी सैलजा ने सरकार पर साधा निशाना

कहा-युवाओं के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़, तय हो जिम्मेदारी

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

चंडीगढ़। एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग) की परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संचालित करने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार को विफल परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि हाल ही में अनेक अभ्यर्थियों को 400 से 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया और वहां पहुंचते ही उन्हें बताया गया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह कोई सामान्य तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक असंवेदनशील और लापरवाह प्रशासनिक तंत्र का उदाहरण है। इसके कारण युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा।

कुमारी सैलजा ने बताया कि जब छात्रों ने यह पाया कि प्रश्न पत्र में पहले पूछे गए प्रश्न दोहराए गए हैं और उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई, तो एसएससी ने यह कहकर टालने की कोशिश की कि छात्र

सरप्राइज हो जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही परीक्षा प्रणाली की गंभीरता और जवाबदेही है?

सांसद ने यह भी कहा कि जब प्रश्न गलत होते हैं, तो उन्हें चुनौती देने के लिए छात्रों से शुल्क वसूला जाता है, जबकि गलती आयोग की होती है। यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और युवाओं के अधिकारों का हनन है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में नीट, यूजीसी नेट और एसएससी जैसी 80 से अधिक परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। सिर्फ इस वर्ष 85 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की है कि एसएससी सहित सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया को स्थिर और विश्वसनीय बनाया जाए। पेपर लीक और प्रश्नों की दोहराव जैसी चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और छात्रों से ली जाने वाली आपत्ति शुल्क को समाप्त किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि अब देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस हर मंच पर इस मुद्दे को उठाती रहेगी और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वह युवाओं के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ को रोके और परीक्षा प्रणाली में सुधार करे।

मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाये-नायब सिंह सैनी

वीटा के बूथ बढ़ाकर लोगों को दिए जाएंगे रोजगार के नए अवसर

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को फसल उत्पादन में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों से फीडबैक लेकर समस्याओं की पहचान करे और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी जैसे क्षेत्र में किसानों की बागवानी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए लघु कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की संभावना पर भी कार्य करे।

मुख्यमंत्री यहां वर्ष 2025-26 की बजट अनाउंसमेंट के संबंध में विभिन्न विभागों की घोषणाओं की प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

कृषि विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया

गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ें। साथ ही, प्राकृतिक खेती से संबंधित अतिरिक्त प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भावना से योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी भावना से उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसान इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। बागवानी विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय के साधन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने नई बागवानी नीति के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने पर बल दिया ताकि इसे अति शीघ्र लागू किया जा सके। बैठक में बताया गया कि राज्य में बागवानी विभाग द्वारा 11 उत्कृष्टता केंद्र पहले से ही संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 3 केंद्र निमार्णाधीन हैं। इस वर्ष के बजट में तीन नए उत्कृष्टता केंद्रों-खजूर के लिए बरवाला (हिसार), लीची के लिए नबीपुर (अंबाला) और स्ट्रॉबेरी के लिए छछरौली (यमुनानगर) की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इन पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर है जिसे निर्धारित समय में पूरा कर लिए जायेगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में वीटा के बूथों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने क्रमवार कृषि विभाग, बागवानी विभाग, वीटा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय दहिया, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश आहुजा, कृषि विभाग के महानिदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नशों के विरुद्ध जंग के 'जरनैल' बनकर गाँवों और शहरों की रक्षा करेंगे डिफेंस कमेटियों के सदस्य-भगवंत सिंह मान

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

लुधियाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम अंतिम दौर में पहुँच चुकी है और गाँवों और शहरों के लिए डिफेंस कमेटियाँ पंजाब में से नशा तस्करी का नामोनिशान मिटा देंगी। यहाँ गाँवों और शहरों के लिए गठित की गई डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने गत 4 फरवरी से राज्य में 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम की शुरूआत की थी, जिसके तहत नशों की बीमारी को जड़ से उखाड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से नशों की सप्लाई लाइन लगभग टूट चुकी है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह इस बात के लिए सभी पंजाबियों का धन्यवाद करते हैं कि सरकार के इस नेक कार्य में सभी पंजाबी बढ़-चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गाँवों और शहरों को भविष्य में नशों की लानत से मुक्त रखने के लिए डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया है। भगवंत सिंह मान ने डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को मुखातिब होते हुए कहा, ह्लमुझे पूरा विश्वास है कि आप नशों के विरुद्ध जंग के जरनैल बनकर गाँवों और शहरों की रक्षा करेंगे। हमने पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने का सपना देखा है और आप सभी के सहयोग से इस सपने को साकार करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम पंजाब की आन, गौरव और स्वाभिमान को बहाल करने का संकल्प लेते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने दी हलके को सौगात, 1 करोड़ 17 लाख की लागत से बनी सड़क का किया उद्घाटन

■ गांव ऊंचा समाना में रावर दादुपुर रंगरान तक करीब पौने तीन किमी लंबी संपर्क सड़क का किया उद्घाटन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी
करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि इलाके की तरक्की के लिए जरूरी है कि सड़के अच्छी हों। पिछले दस सालों में प्रयास किया गया है कि हलके की सभी सड़कें बेहतर स्थिति में हों। पुरानी सड़कों को चौड़ा किया गया है। इसके अलावा करीब 80 नई सडकें बनवाई जा चुकी हैं। पुरानी सड़कों को चौड़ा किया गया। करनाल के ताऊ देवी लाल चौक से यमुना तट तक मेरठ रोड को स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे बनवाकर राज्य सरकार ने इस पर करीब 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आज यह सडक प्रगति में योगदान दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण सोमवार को गांव ऊंचा समाना में रावर दादुपुर रंगरान तक करीब पौने तीन किमी लंबी संपर्क सडक के उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ देकर, पगड़ी पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनवाई गई इस सड़क पर एक करोड़ 17 लाख रुपये खर्च हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बढिया होगा वह अधिक प्रगति करेगा। आज जिस सडक का उद्घाटन किया गया उसके डिजाइन में लोगों की सुविधानुसार कई बार बदलाव किया गया।

ऊंचा समाना में पहले पुराने पुल के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। इसे भी नया बनवाया गया है। राज्य सरकार ने इस पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। फलाईओवर के दोनों ओर रैंप बनाए गए हैं। पहले एक तरफ पीटीसी और दूसरी ओर पक्का पुल धाम होने के कारण अक्सर जाम लगा रहता था। दोनों ओर अंडर पास बनने से अब जाम नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि पक्का पुल के साथ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की हर जायज मांग को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास के मामलों में उन्हें राजनीति पंसद नहीं। सरकार जनता की भलाई के लिए होती है। यह हलका तरक्की की ओर अग्रसर है। इससे 36 बिरादरी को फायदा होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी, रिंग रोड, रेपिड रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब तो घरौंडा जैसे शहर में पांच सितारा होटल भी बनने लगे हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। हलके में कई अस्पतालों और स्कूलों का विस्तार किया गया है। तरक्की का सफर दुगुनी गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हलके में विकास के जो पौधे रोपे गए हैं, भविष्य में भावी पीढ़ी को उनके फल खाने को मिलेंगे और छाया भी नसीब होगी। उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने, पाटीर्बाजी से दूर रहने और बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार देने की अपील की।

इस मौके पर एसडीएम राजेश सोनी, मंडी बोर्ड के कार्यकारी अभियंता विजेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, सतबीर, मंजू खैंची, मनजीत, सरपंच पति सुरेंद्र, ब्रह्मपाल, अजय राणा, निशांत राणा आदि मौजूद रहे।

राजौंद में नाले ऊंचे-सड़कें नीची, सड़क पर जमा कीचड़ और गंदगी से जनता बेहाल

■ चार दिन तक समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा: जेई विजय पीडब्ल्यूडी विभाग

राजौंद के सरकारी अस्पताल, बस सेल्टर, पब्लिक शौचालय, पेगा मार्ग, देवी मंदिर रोड़ टी-प्वाइंट पर जमा कीचड़। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार
राजौंद। राजौंद नगर का हाल बेहाल है और जिम्मेदार विभाग चुप हैं। नगर पालिका राजौंद का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने नाले ऊंचे बनाएं हैं सड़के नीची है। इसलिए बारिश का पानी नालों में नहीं जाता सड़क टूट रही है। सड़कों के किनारे दलदल व कीचड़ जमा हो गया है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कैथल- राजौंद मार्ग पर सिवरेज कार्य लगभग पूरा कर दिया है। लेकिन इस विभाग ने सिवरेज दबाने के बाद इस मार्ग को छोटे वाहनो या दो पहिया वाहन के चलने लायक भी अब तक नहीं बनाया है। जिस कारण से पूरा यातायात डिवाइडर के दूसरी ओर डाइवर्ट हो गया है। जिससे पूरा दिन वाहन चालक, यात्री, नागरिक, स्कूल जाते विद्यार्थी सभी परेशान रहते हैं।

हालात यह हैं कि सरकारी अस्पताल राजौंद के प्रवेश द्वार के आस-पास कीचड़ व दलदल के अंबार लग चुके है, जिससे मरीजों और अस्पताल स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बस क्यू शेल्टर के सामने भी दलदल और गंदगी का साम्राज्य है। यात्री बस का इंतजार किस तरह करें, यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं, पब्लिक शौचालय के बाहर जमा कीचड़ ने आमजन, दुकानदारों और यात्रियों को बेहद परेशान कर रखा है। वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। देवी मंदिर रोड, पेगा रोड टी-प्वाइंट की स्थिति भी बद्तर है। मंदिर में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को कीचड़ और फिसलन भरे मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण यह स्थिति दिन-ब-दिन और बिगड़ती जा रही है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राजौंद में नाले ऊंचे और सड़कें नीची हैं, जो सब समस्याओं की जड़ है। जिससे बरसात का पानी नालों में नहीं जा पाता, और सड़क पर ही कीचड़ का रूप ले लेता है। इसकी सीधी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल की बनती है।

नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो यह मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। लेकिन अफसर और विभाग नदारद हैं।

समस्या के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई विजय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला विभाग के संज्ञान में आ चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए इस सड़क पर जहां जहां पर पानी का भराव है मशीन लगाकर, सफाई की जाएगी, फिर रोडा बिछाया जाएगा, समस्या का स्थाई समाधान किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग नागरिकों की समस्या को दूर करने के प्रति निरंतर प्रयास कर रहा है।

राजौंद में सीवरेज ठेकेदार की लापरवाही से नागरिकों में रोष!

■ सिवरेज व पीने के पानी की पाइप लाइन से हो रहा रिसाव

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार
राजौंद। राजौंद के वार्ड 11, पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज मोहल्ले में सीवरेज कार्य में लगे ठेकेदार की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मोहल्ले में सीवरेज पाइप लाइन और वाटर सप्लाई की पाइप लाइन दोनों लीक हो रही हैं, जिससे पीने योग्य पानी सीधे निमार्णाधीन सीवरेज पाइपों में जा रहा है। यह स्थिति ना केवल नागरिकों की सेहत खिलवाड़ है, बल्कि घरों व दुकानों की नींव को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। स्थानीय निवासियों योगेंद्र सिंह, पिंकी, प्रधान मार्केट यूनियन भीम सिंह राणा, फुल्ला सिंह, सुरेंद्र सिंह, नवीन कुमार, पवन ने बताया कि पाइप लाइन से बहता पानी लगातार बहता रहता है, जो दुकान व मकानों की नींव को खोखला कर रहा है, जिससे दीवारों में दरारें आ गई हैं।

मीडिया ने इस विषय की जानकारी सूचना विभाग के जेई हरि सिंह को दी तो उन्होंने केवल आश्वासन देते हुए कहा कि 'ठीक करवा देंगे।' वहीं सीवरेज ठेकेदार सुनील ने कहा कि जांच कर, ठीक कर देगें। गौरतलब है कि यह समस्या पूरे राजौंद की बनी हुई है।

इस लापरवाही से नाराज नागरिकों ने प्रशासन और सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि अगर शीघ्र समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ, तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों को रोका जा सके।

बंदर पकड़ने के विवाद में डीएसपी कलायत से मिले ठेकेदार व राजौंद पार्षद

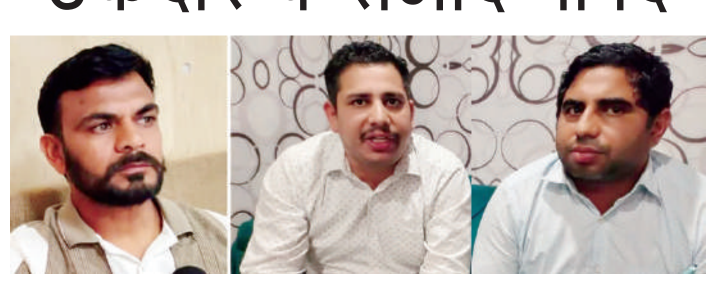

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार
राजौंद। राजौंद नगर में बंदर पकड़ने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के चलते आज ठेकेदार व नगर पार्षद जोनी राणा सहित पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल डीएसपी कलायत के बुलावे पर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों पक्षों ने डीएसपी कार्यालय में अपने-अपने बयान दर्ज करवाए।

पार्षद जोनी राणा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि बंदर पकड़ने के नाम पर नगर में जो अनियमितताएं व गलत व्यवहार सामने आए हैं, उन पर राजौंद नगर पालिका के सभी पार्षद एक मत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा न केवल नगरवासियों पर झूठे आरोप लगाए गए, बल्कि बिना किसी जानकारी के बंदरों को इधर-उधर छोड़ा जा रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। जबकि एक बंदर के पकड़ने का शुल्क 1750 रूपए

■ माफी व पारदर्शिता तक विरोध जारी रहेगा- जोनी राणा

जनता के टैक्स की कमाई में से दिया जाना है। जोनी राणा ने कहा कि पार्षदों की स्पष्ट मांग है कि ठेकेदार को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में जब भी बंदरों को छोड़ा जाएगा, उस स्थान पर पार्षद या प्रतिनिधि को जाने की अनुमति दी जाए। जब तक इन दोनों मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक राजौंद नगर के पार्षद व नागरिक ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

डीएसपी कलायत से इस संदर्भ में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल मामले में कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।

13 अगस्त को भाकियू देशभर में निकालेगी ट्रैक्टर मार्च: रतनमान

■ ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों को लेकर किसानों की लगाई ड्यूटियां

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग
असंध। कैथल रोड स्थित गुरुद्वारा में भारतीय किसान यूनियन की बैठक जोगिंद्र सिंह झीड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।

प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान में देश भर में 13 अगस्त को ट्रैक्टर रोष मार्च निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर रोष मार्च की तैयारियों को लेकर किसानों की ड्यूटियां लगाई।

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी लागू करने, किसानों के कर्ज माफ करने, निजीकरण के खिलाफ, जमीन अधिग्रहण के मामलों और अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ट्रैक्टर रोष मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसको सफल बनाए।

इस अवसर पर कश्मीर सिंह, श्याम सिंह मान, जगबीर संधू, दलबीर सिंह, प्रेम सिंह बल्ला, रणजीत सिंह, महेंद्र सिंह थल, सुखचैन सिंह चौगामा, अमरजीत सिंह, अमरीक सिंह, प्रगट सिंह, गुरनाम सिंह, मेजर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया हासिल

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग
असन्ध। करनाल के एसबीएस स्कूल में आयोजित की गई जिला स्तरीय कला व शब्द गान प्रतियोगिता में करनाल जिले के 43 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

डीएवी पब्लिक असंध के विद्यार्थियों जसकरणदीप सिंह व दमनप्रीत सिंह ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करके ट्राफी अपने नाम की। प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह मान ने इस शानदार उपलब्धि के लिए विजेता विद्यार्थियों तथा स्कूल के कला अध्यापक राजेश कुमार को बधाई दी। स्कूल में पहुंचने पर विद्यार्थियों का प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह मान व स्टाफ सदस्यों ने स्वागत किया।

मान ने कहा कि विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर अपने अभिभावकों व स्कूल का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि कला अध्यापक राजेश कुमार इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अथक परिश्रम के साथ लगे रहे जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल कर ट्राफी जीतने में सफलता हासिल की। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के जरिए ही सफलता हासिल की जा सकती है।

सुखपाल सिंह मान ने कहा कि विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए।

निर्भीक होकर नशे के विरुद्ध 1933 पर दें गुप्त सूचनाएं: डॉ अशोक कुमार वर्मा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग
सोनीपत। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह आईपीएस साहब के दिशा-निर्देशों एवं कुशल मार्गदर्शन में नशे के विरुद्ध जी तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती पंखुड़ी कुमार के आदेश से और पुलिस उपाधीक्षक श्री गजेंद्र कुमार की देखरेख में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा साइकिल पर चलकर नमक लौटा अभियान के अंतर्गत हृदय परिवर्तन संकल्प को गांव-गांव पहुंचाने में जुटे हैं। वे आज सोनीपत पहुंचे। राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें 1412 विद्यार्थियों और 48 शिक्षकों और 7 अन्य कर्मचारियों ने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है।

हरियाणा में ब्यूरो का गठन हो चूका है जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह कर रहे हैं। ब्यूरो द्वारा हरियाणा में वर्ष 2023 में 3823 अभियोग अंकित कर 5930 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चूका है जबकि वर्ष 2024 में 3330 अभियोगों में 5328 नशा तस्करों को सलाखों का मार्ग दिखाया गया है।

इस वर्ष जनवरी से जून तक 1858 अभियोग अंकित करके 3051 अपराधियों को कारागार तक पहुँचाया गया है। इतना ही नहीं इस वर्ष नशा तस्करी में संलिप्त 87 लाख की संपत्ति जब्त की गयी है। उन्होंने आगे बताया कि केवल अपराधियों को पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके साथ दूसरा कार्य जागरूकता का किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश, लोभवश, कर्तव्य विमुख होकर अथवा भ्रष्टाचारी में संलिप्त होकर नशे की दलदल में न चला जाए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक वर्षा खांगवाल आईएएस पदोन्नत

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा
चंडीगढ़। हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) श्रीमती वर्षा खांगवाल आज आईएएस के पद पर पदोन्नत हो गई हैं। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त करने के बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इनको अगले आदेश तक प्रोबेशन पर हरियाणा कैडर आवंटित किया गया है। वर्षा खांगवाल वर्ष 2004 बैच की एचसीएस अधिकारी हैं, इन्होने अपने बैच में एचसीएस परीक्षा को टॉप किया था। श्रीमती खांगवाल वर्तमान में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) के पद पर सेवारत हैं। इससे पहले, वर्षा खांगवाल पंचकूला में अतिरिक्त उपायुक्त रही हैं, इसी प्रकार, वे यूटी चंडीगढ़, हरियाणा के शिक्षा विभाग, शूगर मिल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी समेत कई विभागों में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। खांगवाल की पदोन्नति पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।
संपर्क करें: 9871221635